शिक्षक पोर्टल एवं नवाचार समूह
मध्यप्रदेश

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने दिए संकेत

कोरोना के कारण अब जुलाई में भी नहीं खुलेंगे प्रदेश के स्कूल

पहले 30 जून तक बंद किए गए थे शिक्षण संस्थान

स्टार समाचार | भोपाल

कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण मप्र में जुलाई में भी स्कूल बंद रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्व सहायता समूह से बातचीत के दौरान इसके संकेत दिए है। इसके बाद तय हो गया है कि अब मध्यप्रदेश में जुलाई में स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग 30 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टियां घोषित कर चुका था। इसमें छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी स्कूल से अवकाश दिया गया है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता है। अब जुलाई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन जून के अंत में इसको लेकर एक बैठक होगी। उसके बाद ही आगे के फैसले किए जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि जुलाई में स्कूल बंद ही रहेंगे।

» स्व सहायता समूहों से बातचीत के दौरान सीएम ने कहा- हालात को देखते हुए निर्णय लिया गया

» जून माह के अंत में दोबारा बैठक होगी, सभी पक्षों से बातचीत के बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा

बच्चों के यूनिफार्म बनाएं समूह

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगभग 400 करोड़ रूपए की लागत का विद्यार्थियों के लिए गणवेश बनाने का कार्य, आजीविका विकास के लिए 65 करोड़ रुपए के कार्य, मुर्गी पालन, भेड़ पालन के लिए 12 करोड़ रुपए के कार्य, 90 हजार पीपीई किट निर्माण के लिए 4.56 करोड रुपए के कार्य, टेक होम राशन तैयार करने के लिए 700 करोड़ के कार्य तथा गौशाला, पशु शेड, मुर्गी शेड, बकरी शेड, खेत तालाब, मेड बंधान, वृक्षारोपण आदि के लिए 252 करोड़ रुपए के कार्य दिलाए जाएंगे।

स्कूल खुलने की गाइडलाइन बनाई जा रही

लोक शिक्षण को मानव संसाधन विभाग मंत्रालय की गाइडलाइन के आने का इंतजार है। इसके साथ ही अन्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का आकलन कर एक आदर्श गाइडलाइन तैयार की जाएगी। सभी पक्षों और बच्चों के हित और स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए प्रदेश में स्कूल खोलने का निर्णय लिया जाएगा। उसके बाद ही सरकारी समेत निजी स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े।

मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर दिए संकेत

प्रदेश में जुलाई में भी स्कूल खुलने की संभावनाएं कम

भोपाल ■ एजेंसी

मध्यप्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जुलाई में भी स्कूल बंद ही रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को स्व सहायता समूह से बातचीत के दौरान यह बात कही। इसके बाद तय हो गया है कि प्रदेश में जुलाई में स्कूल नहीं खुलने वाले हैं। इससे पहले स्कूल शिक्षा विभाग 30 जून तक सभी सरकारी और निजी स्कूलों के साथ शैक्षणिक संस्थाओं में छुट्टियां घोषित कर चुका था। इसमें छात्रों के साथ ही शिक्षकों को भी अवकाश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना को देखते हुए अभी हालात ठीक नहीं हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा सकता है। अब जुलाई में भी स्कूल नहीं खुलेंगे, लेकिन जून के अंत में इसको लेकर एक बैठक होगी। उसके बाद ही आगे के फैसले किए जाएंगे। मैं इतना कह सकता हूं कि जुलाई में स्कूल बंद ही रहेंगे। मध्यप्रदेश स्कूल विभाग ने सबसे पहले 4 मार्च को अवकाश घोषित किया था। इसके बाद 30 जून तक छुट्टी घोषित कर दी गई थी।

शिक्षा विभाग को केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार

प्रदेश का शिक्षा विभाग स्कूलों को लेकर केंद्र की गाइडलाइन का इंतजार है। साथ ही, अन्य बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों का आकलन करके एक गाइडलाइन तैयार किए जाने की बात है। इसके बाद ही सरकारी और निजी स्कूलों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। बच्चों की पढ़ाई पर कोई प्रभाव न पड़े, इसलिए सरकारी समेत सभी निजी स्कूलों में ऑनलाइन क्लास ली जा रही हैं।

पेपर से वंचित छात्रों के लिए होगी विशेष परीक्षा

एमपी बोर्ड की स्थगित परीक्षाएं 9 जून से शुरू हो चुकी है। यह परीक्षाएं 16 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षा केंद्र के अंदर जाने से पहले सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की जाती है। छात्रों को प्रवेश पत्र पर प्राचार्य के साइन की भी जरूरत नहीं है। इतना ही नहीं, कोरोना के कारण पेपर नहीं दे पाने वाले छात्रों के लिए विशेष परीक्षा आयोजित की जाएगी।

भोपाल जिले में पाए गए 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज

भोपाल। भोपाल जिले में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार वृद्धि जारी है। शनिवार को 76 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। इनकी कॉन्ट्रेक्ट हिस्ट्री निकाली जा रही है। इन सभी संक्रमित व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया जा रहा है। कोरोना संक्रमित मरीजों के घर को एपिक सेंटर घोषित कर एक किमी क्षेत्र को कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित किया गया है। भोपाल में अब तक 69 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। भोपाल में अब तक कुल पॉजिटिव सैंपलों की संख्या 2332 पहुंच गई है। वहीं प्रदेश युवक कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल चौधरी के कोरोना संक्रमित होने की खबर है।

राजनीति शास्त्र के पेपर में पूछा सवाल, आजाद कश्मीर क्या है

एमपी बोर्ड की 12वीं की परीक्षा में 'आजाद कश्मीर' पर फिर बवाल

शहर प्रतिनिधि, भोपाल। मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की बारहवीं परीक्षा के शनिवार को हुए राजनीति शास्त्र के पेपर में आजाद काश्मीर का सवाल पूछे जाने पर फिर से बवाल शुरू हो गया है। तीन महीने पहले दसवीं परीक्षा में सामाजिक विज्ञान के पेपर में आजाद कश्मीर के संबंध में सवाल पूछा गया था। मार्च में सवाल पूछे जाने पर भाजपा ने आपत्ति जताई थी। जिसके बाद पेपर सेटर व माडरेटर को निलंबित किया था। इसके साथ ही सामाजिक विज्ञान के पेपर में आजाद कश्मीर के पूछे जाने वाले सवाल निरस्त कर दिए थे। यह सवाल दस नंबर के थे। सामाजिक विज्ञान का पेपर 100 के बजाय 90 अंक कर दिया था। अब दोबारा बारहवीं की परीक्षा में सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

बारहवीं परीक्षा में यह पूछा गया आपत्तिजनक सवाल

मप्र बोर्ड की बारहवीं परीक्षा में शनिवार को राजनीति शास्त्र का पेपर था। इसमें प्रश्न क्रमांक 6 में दो नंबर का प्रश्न पूछा गया है। 'आजाद कश्मीर क्या है'? यह सवाल पूछे जाने पर कांग्रेस ने आपत्ति लेते हुए पेपर बनाने वाले दोषियों पर कार्यवाही की मांग की है।

दसवीं में भी पूछा गया था सवाल 3 शिक्षक हुए थे निलंबित

मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल की दसवीं बोर्ड परीक्षा में बीती सात मार्च को सामाजिक विज्ञान का पेपर था। पेपर में 'आजाद कश्मीर' को लेकर दो सवाल पूछे गए थे। प्रश्न संख्या-4 में सही जोड़ी में मिलाने को लेकर आजाद कश्मीर का विकल्प दिया गया। वहीं, प्रश्न संख्या-26 में भारत के मानचित्र में 'आजाद कश्मीर' दर्शाने के लिए कहा गया था। परीक्षा के बाद सियासत तेज हुई, तो कमलनाथ सरकार पर विपक्ष में रही भाजपा ने हमला बोल दिया था। तत्कालीन मुख्यमंत्री व तत्कालीन स्कूल शिक्षामंत्री ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। मामले में प्रश्न-पत्र सेट करने वाले नितिन सिंह जाट, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रायसेन एवं प्रश्न-पत्र मॉडरेट करने वाले रजनीश जैन, व्याख्याता शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तेन्दूखेड़ा नरसिंहपुर ने अपेक्षित सर्तकता नहीं बरतने पर निलंबित कर दिया था।

माशिमं में ऐसे किए जाते पेपर सेट

माध्यमिक शिक्षा मंडल के अनुसार, पेपर सेट करने के लिए तीन स्तरीय मॉडरेशन कमेटी बनाई जाती है। कमेटी का प्रमुख 5 सदस्यों का पैनल बनाता है। सभी सदस्य अलग-अलग पेपर तैयार करते हैं और इसे कमेटी के प्रमुख के पास जमा करते हैं। फिर प्रमुख 2 सदस्यों से फाइनल पेपर सेट कराता है, इसे प्रूफ के लिए दिया जाता है।

राजनीति शास्त्र के पेपर में शनिवार को पूछा गया आजाद कश्मीर के संबंध में सवाल पूर्व में 2015 व 2018 के पेपर में भी आए है। यह सवाल किताब में है। बीती सात मार्च को दसवीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर में आजाद कश्मीर को लेकर सवाल नक्शे संबंधित था। वह आपत्तिजनक था। बारहवीं के पेपर में पूछा गया सवाल किताब के अनुसार है।

अनिल सुचारी, सचिव मप्र माध्यमिक शिक्षा मंडल

महामारी में छिपे घातक खतरे के संकेत, बीमा करना होगा सबसे बड़ा विवेक

विद्यार्थियों से लेकर समस्त शिक्षण के स्टाफ ने मांगा सामूहिक बीमा

शिक्षण संचालनालय ने कहा शासन आदेश दे तो व्यवस्था करने को तैयार

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

दिल दहला रही कोरोना जैसी घातक बीमारी से बढ़ते लगातार खतरे के संकेत से शिक्षक बेचैनी हो उठे हैं। इन हालातों से स्कूलों में बच्चों से लेकर समस्त शैक्षणिक स्टाफ का सामूहिक बीमा कराने की मांग उठी है। इसके लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी पत्र लिखा गया है।

राज्य आदर्श शिक्षक मंच ने इस संबंध में मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। कहा गया है कि यह बड़ा संकट काल है। स्कूलों में शिक्षकों से लेकर बच्चों को बुलाना किसी जोखिम से कम नहीं है। नतीजतन एक साथ सभी का बीमा होना चाहिए। इस संगठन ने तर्क भी रखा है कि पहले भी स्कूलों में बच्चों के बीमा हुआ करते थे। व्यवस्था में परिवर्तन कर समस्त शैक्षणिक स्टाफको भी बच्चों के साथ शामिल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर कक्षा में किसी एक विद्यार्थी को कोरोना संक्रमण होता है तो उसकी चैन शाला में पढ़ने वाले सभी बच्चे और शिक्षकों से जुड़े गी। संगठन का कहना है कि शासकीय के अलावा अशासकीय विद्यालयों में भी यह प्रबंध होना चाहिए। इसलिए तत्काल महामारी के खतरे को देखते हुए सामूहिक बीमा कराया जाए । स्कूल खुलने के पहले यह कार्य किया जाना सभी के हित में होगा ।

राज्य में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण: भगवती प्रसाद

राज्य आदर्श शिक्षक संघ के अध्यक्ष भगवती प्रसाद पंडित का कहना है कि प्रदेश में सम्भवत: जुलाई माह में स्कूल खुलने की पूरी सम्भवना है । राज्य में कोरोना महामारी का संक्रमण अभी थमा नहीं है और भविष्य में भी पूरी तरह सुधार की संभावनाएं कम ही बताई जा रही है। इसलिए ऐसी स्थिति में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए सावधानी के साथ ही बीमा की सुरक्षा भी जरूरी है । सरकारी एवम अनुदान प्राप्त स्कूलों का खर्च सरकार वहन करे तथा शासन आदेश जारी कर निजी स्कूलों के प्रबंधन से कहे कि वे सभी का बीमा अनिवार्य रूप से अपने व्यय पर करें। उन्होंने कहा है कि दोनों का बीमा होने पर उन्हें स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी मिलेगी और उनके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी ।

बीमा योजना लाना महती आवश्यकता

वरिष्ठ शिक्षक नेता मुरारी लाल सोनी का कहना है कि पूर्व में सरकारी स्कूलों के बच्चों का नाममात्र शुल्क में सामूहिक बीमा किया जाता था । कोरोना महामारी की भयाहवकता के मद्देनजर अब इस योजना की महती आवश्यकता है । इसे पुन: प्रारम्भ कर तथा नए संशोधन के साथ इसका दायरा बढ़ाकर इसमें प्रदेश के समस्त सरकारी ए निजी स्कूलों के बच्चो ए शिक्षकों के साथ स्कूली स्टाफको भी शामिल किया जाना चाहिए । यह योजना सरकारी शिक्षकों एवं स्कूली स्टाफ के लिए वर्तमान में प्रचलित बीमा योजना के अतिरिक्त होना चाहिए। इससे जहां सामाजिक सुरक्षा गारंटी को बल मिलेगा वही यदि किसी के साथ बीमारी से कोई अकस्मात हादसा होता है तो पीड़ित परिवार को बड़ा आर्थिक बल मिलेगा।

शासन आदेश देगा तो उसका पूरा पालन होगा: जयश्री कियावत

इस संबंध में लोक शिक्षण संचालनालय की आयुक्त जय श्री कियावत का कहना है कि यदि शासन आपदा के इस दौर में बीमा योजना लागू करने का आदेश देता है तो उसका पूरा पालन किया जाएगा। श्रीमती कियावत के अनुसार हम भी चाहते हैं कि हमारे विद्यालयों में सभी बच्चे और पूरा शैक्षणिक स्टाफपूरी सुरक्षा के साथ कार्य करें। इस कारण ऐसे कार्य यदि सरकार करती है तो उसमें पूरा सहयोग करना हमारी जवाबदारी है। जयश्री कियावत का कहना है कि शासन की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं स्कूलों में संचालित हो रही हैं उनका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है।

10 वीं का रिजल्ट 30 जून तक घोषित करेगा माशिमं

भोपाल (आरएनएन)। अनेक चुनौतियों और कठिनाइयों के बीच परीक्षण संपादित करवा रहा माध्यमिक शिक्षा मंडल हाई स्कूल का रिजल्ट इसी माह के अंत तक घोषित कर देगा। जबकि हायर सेकेंडरी के नतीजों में पूरा जुलाई महीना निकल सकता है।माध्यमिक शिक्षा मंडल का कहना है कि हाई स्कूल का मूल्यांकन अंतिम चरणों में है। जनरल प्रमोशन देने के बाद विद्यार्थियों की मेरिट और अंकों का आंकलन हो रहा है। मंडल के अनुसार 25 जून तक रिजल्ट बनकर तैयार हो जाएगा। बोर्ड के अनुसार कोरो ना आपदा को लेकर मूल्यांकन कई जिलों में प्रभावित हुआ है। इसके बावजूद शिक्षकों की मेहनत वाकई में सराहनीय है। बोर्ड का कहना है कि 10वीं का रिजल्ट 30 जून तक घोषित कर दिया जाएगा। इसकी विधिवत तैयारियां चल रही है। 12वीं के रिजल्ट में अभी समय लगेगा। 16 जून तक हायर सेकेंडरी के शेष प्रश्न पत्रों की परीक्षा संपन्न होगी। उसके बाद यह तय होगा कि यह उत्तर पुस्तिकाएं किस जिले में जांच के लिए भेजी जाए। मंडल इस बात पर भी विचार कर रहा है कि अभी तक जितनी परीक्षा बारहवीं की संपन्न हुई। उतने विषयों की कॉपियां जिन जिलों में पहुंची है। उन्हीं जिलों में यह कॉपियां भी भेजी जाए। इसके लिए निष्कर्ष निकाला जा रहा है। मंडल में अधिकारियों का कहना है कि हायर सेकेंडरी का रिजल्ट जुलाई अंत तक ही घोषित हो पाएगा। इस संदर्भ में मंडल के सचिव का कहना है कि 12वीं का रिजल्ट हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द घोषित हो। ताकि विद्यार्थियों को कॉलेजों में आसानी से दाखिला मिल सके।

12वीं के नतीजे जुलाई अंत तक आने की संभावना

पदोन्नति का मसौदा मंत्रालय में झूला आपसी कलह से सिस्टम लाभ देना भूला

कर्मचारियों ने कहा संगठन नेताओं के स्वार्थ और अंतर्द्वंद से करोड़ों का नुकसान

मुख्यमंत्री की घोषणाओं के अमल में शिक्षक और कर्मचारियों के नेता बाधक

भोपाल ■ राज न्यूज नेटवर्क

प्रदेश में शिक्षकों और अन्य संवर्ग ई कर्मचारियों के प्रमोशन में आ रही रुकावट के पीछे कहीं ना कहीं अपने ही विभीषण का रोल अदा कर रहे हैं। यह आरोप प्रदेश के उन तबकों ने लगाया है जो दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में निष्ठा के साथ समाज की सेवा में जुटे हुए हैं।

इनका कहना है कि प्रदेश में योग्यताधारी शिक्षकों सहित अन्य विभागों में उच्च पद के समकक्ष क्रमोन्नति, समयमान वेतनमान प्राप्त कर्मचारियों को अनार्थिक पदनाम की मुख्यमंत्री द्वारा की गई मंचीय घोषणा अटक कर रह गई है। मंजिल से दूर मंत्रालय में मंथर गति से टेबल दर टेबल पदनाम फाइल चलने का क्रम बदस्तूर जारी है, लेकिन आदेश जारी नहीं हो पा रहे हैं। आरोप लगाया गया है कि पदोन्नति पदनाम में शिक्षकों के बीच उभरते अनेक विरोधी गुट इस लाभ में बाधक बन रहे हैं। प्रदेश के दूरस्थ ग्रामीण अंचलों में पदस्थ शिक्षक और कर्मचारियों ने कहा कि अब संगठनों का कोई औचित्य नहीं रहा है। अपनी वास्तविक लड़ाई लड़ने की बजाए संगठनों के नेता प्रमुख राजनीतिक दलों की विचारधारा से जुड़ने में सबसे ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। यही कारण है कि लगातार कर्मचारियों को मासिक करोड़ों का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। आपस में लड़ाई मची हुई है और इसका फायदा सरकार में बैठे आला अधिकारी उठा रहे हैं।

बिना प्रमोशन के सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षक कर्मचारी : कन्हैयालाल

उपाध्यक्ष कन्हैयालाल लक्षकार एवं सचिव जगमोहन गुप्ता ने बताया कि कर्मचारियों की पदोन्नति प्रकरण आरक्षण के पेंच से सर्वोच्च न्यायालय में विगत वर्षों से लंबित है। इस पर मप्र सरकार लगभग छह करोड़ खर्च करने के बाद भी न्याय की प्रत्याशा में है। लेकिन निकट भविष्य में न्याय मिलना संभव प्रतित नहीं हो रहा है। इस अवधि में लगभग एक लाख शिक्षक, कर्मचारी नियुक्ति के 30.40 साल बाद उसी पद से बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत हो चुके है। हजारों शिक्षक, कर्मचारियों के सेवानिवृत होने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इसके फोरी तौर पर समाधान के लिए अनार्थिक मांग पदनाम एक समाधान है।

भ्रष्ट हो चुके हैं शिक्षक और कर्मचारी संघों के नेता

मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रमोद तिवारी का कहना है कि शिक्षक और कर्मचारियों के संगठन नेता अब अपना ईमान खो चुके हैं। एकजुटता बची नहीं है। यही कारण है कि प्रमोशन के लिए भटकना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार इसका फायदा उठा रही है। उन्होंने कहा कि पदनाम के मामले में अपना स्पष्ट मत रखते हुए मौजूदा मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने 5 व 23 सितम्बर 2017 को शिक्षकों के लिए मंचीय घोषणा की थी। विडम्बना है कि कई माननीयों द्वारा भी इसके पक्ष में घोषणा कर प्रयास के आश्वासन सार्वजनिक मंचों से दिए जा चुके है। 8 सितम्बर 2019 को तात्कालिक विधायक द्वय हरदीपसिंह डंग सुवासरा कांग्रेस अब निवृत्तमान भाजपा सदस्य अनिरूद्ध माधव मारू भाजपा मनासा ने मप्र तृतीय वर्ग शास कर्म संघ के संपन्न संभागीय सम्मेलन मनासा में एक ही मंच से घोषणा कर प्रयास के आश्वासन दिये थे। घोषणा का पालन मुख्यमंत्री अपने उस कार्यकाल में व सत्ता परिवर्तन के बाद तात्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ अपने वचनपत्र के पालन में पूरा नहीं करवा पाये।

मौजूदा मुख्यमंत्री के समय आया था प्रमोशन में नया मोड़: जगमोहन गुप्ता

मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव जगमोहन गुप्ता के अनुसार संयोग से फिर शिवराजसिंह चौहान मुख्यमंत्री पद पर काबिज है, लेकिन पदनाम अभी भी शिक्षकों, कर्मचारियों के सामने मुंह बाये खड़ा है। शिवराज सिंह चौहान किस समय ही पदोन्नति आें का मामला कोर्ट में पहुंचा था। उन्होंने कहा कि अब शासन-प्रशासन की नूराकुश्ती समाप्त कर उप चुनाव की आचार संहिता लागू होने के पूर्व तत्काल इसका समाधान करते हुए आदेश होना चाहिए। यदि ऐसा तकनीकी पेंच के चलते संभव नहीं हो पा रहा है तो जवादारी द्वारा सार्वजनिक रूप से स्वीकारोक्ति कर स्पष्ट किया जाना चाहिए की असली रूकावट कहां है, इसका सर्वोच्च प्राथमिकता से समाधान निकाला जाए।

हजारों कर्मचारियों और शिक्षकों में निराशा का भाव: अलका शर्मा

मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस में महिला मोर्चा की अध्यक्ष अलका शर्मा का कहना है कि प्रमोशन पर पाबंदी होने से हजारों शिक्षक, कर्मचारी प्रतिमाह बगैर पदोन्नति के सेवानिवृत हो रहे हैं। इससे हताश, निराश लाखों शिक्षकों, कर्मचारियों में भारी नाराजगी व आक्रोश व्याप्त होकर मनोबल कमजोर हुआ है। वहीं स्वस्थ लोकतंत्र में माननीयों एवं मुख्यमंत्री की घोषणा पालन की उपेक्षा चिन्ताजनक व अक्षम्य है। अलका शर्मा का कहना है कि सरकार को अविलंब उन सब वर्गों को पदोन्नति देना चाहिए। जिनका प्रमोशन करने में कोई बीमार नहीं आ रहा है।

शैक्षिक नवाचार प्रतियोगिता आज से 20 जून तक

शिक्षक बताएंगे कोरोना संकटकाल में कैसे निभाया अपना दायित्व और कौन से नवाचार किए

भोपाल ■ एजेंसी

कोरोना संकटकाल में अपने शिक्षकीय दायित्व को निभाने के लिए शिक्षकों ने क्या किया और कौन कौन से शैक्षिक नवाचार किए। इस सिलसिले में राज्य शिक्षा केंद्र स्कूल शिक्षा विभाग ने 14 से 20 जून की अवधि में शिक्षकों के लिए 'शैक्षिक नवाचार' विषय पर प्रतियोगिता का आयोजन किया है।

इस प्रतियोगिता में सहभागिता के लिए शिक्षकों को कोरोना लॉकडाउन अवधि में स्वयं के दायित्व निर्वहन के अनुभवों के बारे में या इस दौरान स्वयं के द्वारा किए गए शैक्षिक नवाचार के बारे में 2 से 3 पृष्ठों में लिखकर व्हाटसएप नंबर 9968556947 पर प्रेषित करना होगा। चयनित प्रविष्टियों को राज्य स्तरीय प्रकाशन में स्थान प्राप्त होने के साथ ही शासन द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि, राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा विगत 17 मई से विभिन्न प्रतियोगिताओं का साप्ताहिक रूप से आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सर्व प्रथम 17 से 23 मई तक 'लॉकडाउन डायरी' प्रतियोगिता कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए, 24 से 30 मई तक 'पीढ़ियों का ज्ञान/धरोहर' प्रतियोगिता परिवार के बड़े-बुजुर्गों एवं ग्रेंड पैरेंटस के लिए, 31 मई से 6 जून तक 'परवरिश' प्रतियोगिता पालकों के लिए तथा चतुर्थ सप्ताह 7 से 13 जून की अवधि में 'नया हुनर - मैंने सीखा' प्रतियोगिता सभी कक्षाओं के स्कूली विद्यार्थियों के लिए आयोजित की जा चुकीं हैं। इसी कड़ी में अब 14 से 20 जून की अवधि में अंतिम सप्ताह में अंतिम प्रतियोगिता के रुप में शिक्षकों के लिए शैक्षिक नवाचार प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है।

आकाशवाणी और वन्या रेडियो से प्रसारित हो रहें हैं शैक्षिक कार्यक्रम

लॉकडाउन के कारण एमपी में रेडियो स्कूल से घर पर ही हो रही है पढ़ाई

स्टार समाचार | भोपाल

कोरोना संकटकाल में पढ़ाई की निरंतरता के लिए राज्य शिक्षा केन्द्र, स्कूल शिक्षा विभाग के द्वारा प्रारंभिक कक्षाओं के विद्यार्थियों की शैक्षिक निरंतरता के लिए रेडियो स्कूल कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

यह कार्यक्रम आकाशवाणी के प्रदेश में स्थित सभी प्रसारण केन्द्रों के साथ ही वन्या सामुदायिक रेडियों के सभी प्रसारण केन्द्रों से भी, सोमवार से शनिवार तक प्रातः 11 से 12 बजे तक प्रसारित होता है। इस कार्यक्रम में प्रारंभिक कक्षाओं के लिए रोचक कहानियां एवं पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रमों का प्रसारण किया जा रहा है। जिससे स्कूल बंद होने पर भी विद्यार्थी अपने घरों पर रहकर ही अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए हैं।

सुबह 11 बजे से 12 बजे तक प्रसारित होता है कार्यक्रम

आदिम जाति कल्याण विभाग के वन्या सामुदायिक रेडियो केन्द्रों से भी रेडियो स्कूल कार्यक्रम का प्रसारण विगत 8 जून से प्रारंभ किया गया है जिसके तहत वन्या सामुदायिक रेडियो के भावरा जिला अलिराजपुर (भीली), खालवा जिला खण्डवा (कोरकू), नालछा जिला धार (भीली), मेघनगर जिला झाबुआ (भीली), सेसईपुरा जिला श्योपुर (सहरिया), चिचोली जिला बैतूल (गोंडी), तामिया छिन्दवाड़ा (भारिया), चाड़ा जिला डिण्डोरी (बैगानी) से भी सोमवार से शनिवार तक रोजाना प्रात– 11 बजे 12 बजे तक रेडियो स्कूल कार्यक्रम प्रसारित किया जा रहा है।

परीक्षा की जगह होगा मासिक मूल्यांकन

भोपाल। कोरोना के संक्रमण और लॉकडाउन के कारण पढ़ाई का पूरा सिस्टम ही बिगड़ गया है। पढ़ाई का सिस्टम कब तक बिगड़ा रहेगा अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इस साल पहली से लेकर कॉलेज तक के बच्चों की पढ़ाई ठप है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन पढ़ाई कराई जा रही है, लेकिन उसकी हकीकत भगवान ही जाने। ऐसे में स्कूल शिक्षा विभाग ऐसी योजना बना रहा है कि जब स्कूल ही नहीं खुले हैं और पढ़ाई नहीं हुई तो बच्चों की तिमाही और छमाही परीक्षा कैसे ली जाएगी। इसलिए अब सरकारी स्कूलों के बच्चों का मासिक मूल्यांकन होगा। इस साल से 9वीं व 11वीं कक्षा में प्री-वार्षिक परीक्षाएं शुरू की गई थीं। वहीं 10वीं और 12वीं में भी इस साल से फर्स्ट प्री-बोर्ड परीक्षाएं शुरू की गईं। इस बार कक्षाएं नहीं लगने के कारण यह सभी परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी। रश्मि अरूण शमी ने कहा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से पढ़ाई हो रही है, इसलिए हर माह बच्चों का मूल्यांकन होगा। तिमाही व छमाही जैसी परीक्षाएं लेना सही नहीं होगा।

आवास सहायता के लिए किराया नामा नोटरी कराने की जरूरत नहीं

आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को मिली राहत

नव स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

प्रदेश के आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों के लिये अच्छी खबर है। अब किराए का घर लेकर पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों को राज्य सरकार से आवास सहायता लेने के लिए ना तो किरायानामा नोटराईज करने की जरुरत होगी ना ही उसे स्टाम्प पेपर पर तैयार करने की आवश्यकता होगी। सरकार ने इस साल से इस नियम से छूट प्रदान कर दी है। आदिवासी वर्ग के विद्यार्थियों को राज्य सरकार छात्रावास निःशुल्क उपलब्ध कराती है। जिन स्थानों पर छात्रावास, आश्रम नहीं होते है वहां ये विद्यार्थी किराए का आवास लेकर भी पढ़ाई कर सकते है। सरकार आदिवासी विद्यार्थियों को निजी भवनों का किराया उपलब्ध कराती है। लेकिन इसके लिए अभी तक आदिवासी विद्यार्थियों को निजी आवास के किराए का भुगतान प्राप्त करने के लिए योजना के तहत किरायानामा का अनुबंध पत्र स्टाम्प पेपर पर नोटराईज कराकर देना होता है।

यह हुआ बदलाव

अब आवास सहायता योजना के तहत छात्र से किरायानामा मकान मालिक एवं किराएदार(विद्यार्थी)के बीच द्विपक्षीय स्वहस्ताक्षरित घोषणा पत्र के रुप में लिया जाएगा इसे नोटराईज कराने या स्टाम्प पेपर पर लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। आयुक्त आदिवासी विकास ने प्रदेश के सभी कलेक्टरों, सहायक आयुक्त, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग को पत्र लिखकर नए नियम का पालन करने के निर्देश दिए है।

7 हजार अतिथि शिक्षक 45 सौ विद्वान, 1000 अतिथि व्याख्याता दिखाएंगे दम

नव स्वदेश संवाददाता ■ भोपाल

एक तरफ देश-प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते तालाबंदी का दौर चल रहा है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश ग्वालियर-चंबल उपचुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। इसी बीच अतिथ शिक्षक-विद्वान व व्याख्याताओं के नियमितिकरण का मुद्दा भी जोर पकड़ता जा रहा है। मालूम हो प्रदेश के तीन अलग अलग संगठनों के करीब 75 हजार 500 अतिथियों का फिजिकल आंदोलन भले बंद हो, लेकिन सोशल मीडिया पर ई-प्रोटेस्ट की कैंपेनिंग लगातर जारी है। अतिथि संगठनों का कहना है हम लगातार सरकार के समक्ष नियमितिकरण की मांग को रख रहे हैं। बावजूद इसके सरकार हमारी मांगों को अनसुना करती है तो उसे इसके अंजाम भुगतने पडेगे।

गौरतलब है नियमितिकरण की मांग को लेकर राजधानी के शाहजहांनी पार्क में 100 दिन से अधिक समय तक अतिथि शिक्षक व विद्वानों ने फिजिकल धरना प्रदर्शन किया था, कारोना वायरस के चलते उन्हें सरकार के नीति विरोधी आंदोलन को फिजिकल रूप से निरस्त करना पड़ता था, लेकिन अतिथिओं का सोशल मीडिया पर ई-प्रोटेस्ट कैंपेन लगातार जारी है। इस कैंपेन में प्रदेश के 70 हजार अतिथि शिक्षक,4500 अतिथि विद्वान एवं 1000 हजार अतिथि व्याख्याता शामिल हैं। इनकी मांगे है कि सरकार वर्तमान वेतनमान पर ही नियमितिकरण कर दे। अन्यथा ग्वालियर-चंबल उपचुनाव में सरकार अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे।

इनकी अपनी बात

“ पिछले पांच महीने से मानदेय हीं नहीं मिला। गुना जिले के अतिथियों का मानदेय सितंबर महीने से नहीं मिला। इसके चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं एवं तेंदूपत्ता तोड़ने बेगारी करने पर विवश हैं। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि उनका शेष मानदेय शीघ्र दिलाया जाए।

सुनील परिहार, प्रदेशाध्यक्ष, अतिथि शिक्षक संघ

“ पूर्ववर्ती सरकार ने विद्वानों के हित में नियमितिकरण को लेकर नोटशीट जारी की थी, उसे जल्द मूर्त रूप दिया जाए।

देवराज सिंह, प्रदेशाध्यक्ष, अतिथि विद्वान संघ

“ अतिथि व्याख्याता संघ की मांग है कि सरकार पिछले मानदेय का भुगतान 30 हजार बेसिक सैलरी पर करे। इसके अलावा नियमितकरण के मामले में नीति स्पष्ट करें।

सुघर सिंह जाटव, संयोजक, अतिथि व्याख्याता संघ

ऑनलाइन कक्षाओं पर लग सकती है रोक

भोपाल। कर्नाटक की तर्ज पर मप्र में भी प्रायमरी की ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लग सकती है। प्रदेश के सरकारी व निजी स्कूलों में एलकेजी से लेकर पांचवीं कक्षा तक ऑनलाइन कक्षाओं पर रोक लगाने को लेकर विचार चल रहा है। इस संबंध में मप्र स्कूल शिक्षा विभाग जल्द ही निर्णय ले सकता है।

16 से 30 जून तक ऑनलाइन अपलोड करने होंगे दस्तावेज

भोपाल। उमा शिक्षक भर्ती के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग ने प्रथम चक्र की अस्थाई चयन सूची और प्रतीक्षा सूची जारी कर दी है। यह सूची 2220 पदों के लिए जारी की गई है। विभाग ने प्रतीक्षा सूची में भी इतने ही उम्मीदवारों को शामिल किया है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर उम्मीदवार 16 से 30 जून तक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। साथ ही स्कूलों के विकल्प का चयन करना होगा। सत्यापन प्रक्रिया 8 से 20 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। विभाग 15 हजार पदों पर एक ही राउंड में एक साथ भर्ती कर रहा है।

डिजिलिप द्वारा बच्चों को वीडियो दिखाकर पढ़ाया गया पाठ

रामपुर, (नि.प्र.)। जन शिक्षा केन्द्र कन्या रामपुर बाघेलान के अन्तर्गत शासकीय माध्यमिक विघालय नेमुआ वॉर्ड क्रमांक 5 में रामबली सिंह और ललित नारायण ताम्रकार के द्वारा बच्चो के घर जाकर 11-6-20 को डिजिलिप के द्वारा बच्चो को वीडियो दिखाकर गणित के प्रश्नों को हल करने में मदद की गई। बच्चो को पेन और कापी देकर उन्हें पहाड़ा लिखने का काम पूरा किया गया।12-6-20 और 13-6-20 को एक पेज हिंदी और एक पेज अंग्रेजी का होम वर्क दिया ।

आयुक्त का आदेश दरकिनार कर भमरहा के लेखापाल को कैसे भेजा मैहर व चित्रकूट ?

फिर सामने आई जिला संयोजक की मनमानी

जागरण सतना। जनजातीय कार्य विभाग में प्रभारी जिला संयोजक कमलेश्वर सिंह की मनमानी थमने का नाम नही ले रही। हर दिन कोई न कोई नया मामला सामने आ जाता है। इसके बाद भी संबंधित प्रभारी जिला संयोजक की गतिविधिया थमने का नाम नही ले रही। हैरानी इस बात की है कि आदिवासी विकास आयुक्त म.प्र. शासन ने निर्देश जारी करते हुए कहा था कि एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में बगैर उनकी जानकारी के ना तो कोई पदस्थापना की जायेगी और न ही किसी को हटाया जायेगा। लेकिन इसके बाद भी व्यावख्याता पद वाले प्रभारी जिला संयोजक कमलेश्वर सिंह ने इन आदेशो को दरकिनार करते हुए जहां थोक में तबादले कर सुर्खिया बटोरी है। वहीं उन्होने भमरहा विद्यालय में पदस्त लेखापाल आशुतोष मिश्रा को पहले तो एकलव्य विद्यालय मैहर भेजा इसके बाद उन्हे तीन दिन के लिए चित्रकूट एकलव्य विद्यालय का कार्यभार भी देने के आदेश जारी कर दिया। उल्लेखनीय है कि आशुतोष मिश्रा जब आदिवासी विकास काम देख रहे थे तब इन पर कई आदिवासी उपभोक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाये थे। मगर उन्हे एकलव्य विद्यालय मैहर एवं चित्रकूट के लेखापाल का दायित्व सौपा गया है। इस आदेश पर कई तरह के सवाल उठना लाजमी है।

मैहर से 140 किलोमीटर दूर है चित्रकूट

मैहर एकलव्य विद्यालय में पदस्थ किये गये लेखापाल आशुतोष मिश्रा को चित्रकूट का वित्तीय एवं लिपिकीय प्रभार यू तो पहले से ही कई तरह के सवाल उठा रहा है मगर हैरानी इस बात की भी कि मैहर से चित्रकूट की दूरी तकरीबन 140 किलोमीटर है। यदि उन्हे वित्तीय प्रभार देना ही था तो और भी कोई कर्मचारी का नाम दिया जाता सकता था जो चित्रकूट से नजदीक हो।

मेस व्यवस्था का पूरा जिम्मा आशुतोष पर

सूत्र बताते है कि मैहर में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं चित्रकूट में संचालित एकलव्य विद्यालय में रहने वाले सभी विद्यार्थियों को खाने पीने से संबंधित जो भी व्यवस्थाएं होती है। वह सारा दायित्व आशुतोष पर सौपा गया है। आखिरकार संबंधित विद्यालयों में प्राचार्य होने के बाद भी यह व्यवस्था लेखापाल क्यों और कैसे देख रहे है। यह एक बहुत बडा सवाल है सूत्र यह भी बताते है मैहर में तकरीबन 4 सौ और चित्रकूट में लगभग दो सौ विद्यार्थी रहते है।

2021 में होगी पोस्टिंग

अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला बनीं अनमोल

वॉशिंगटन, जेएनएन। सेकेंड लेफ्टिनेंट अनमोल नारंग अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली पहली सिख महिला होंगी। उन्होंने वेस्ट प्वॉइंट मिलिट्री एकेडमी से न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में चार साल की डिग्री पूरी की है। नारंग एयर डिफेंस सिस्टम के क्षेत्र में काम करना चाहती हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मौजूदगी में रविवार को उनकी ग्रेजुएशन सेरेमनी होगी। ग्रेजुएशन के बाद ओक्लोहोमा के फोर्ट सिल में उन्हें बेसिक ऑफिसर लीडरशिप कोर्स (बीओएलसी) पूरा करना होगा। इसके बाद वे अमेरिकी एयरफोर्स ज्वॉइन करेंगी। नारंग की पहली पोस्टिंग जनवरी 2021 में जापान के ओकीनावा में होगी। यहां अमेरिकी एयरबेस है। बता दें कि नारंग जॉर्जिया के सिख परिवार से हैं।

ऑनलाइन पढ़ाई के लिए 56 प्रतिशत बच्चों के पास स्मार्टफोन नहीं

स्कूली छात्रों पर किए गए एक अध्ययन के मुताबिक करीब 56 प्रतिशत बच्चों के पास स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है, जबकि लॉकडाउन के दौरान ई-लर्निंग के लिए यह बेहद जरूरी है। यह अध्ययन 42,831 स्कूली छात्रों पर किया गया। कोविड-19 के बीच परिदृश्य - जमीनी स्थिति एवं संभावित समाधान शीर्षक वाला अध्ययन बाल अधिकार मुद्दों पर काम करने वाले गैर सरकारी संगठन स्माइल फाउंडेशन ने किया है। इस अध्ययन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी की उपलब्धता का विश्लेषण करना है। अध्ययन के नतीजों से यह प्रदर्शित होता है कि सर्वेक्षण में शामिल किए गए 43.99 प्रतिशत बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध है और अन्य 43.99 प्रतिशत छात्रों को बेसिक फोन उपलब्ध है, जबकि 12.02 प्रतिशत के पास इन दोनों में से कोई फोन नहीं है। अध्ययन में कहा गया कि 56.01 प्रतिशत बच्चों को स्मार्टफोन उपलब्ध नहीं है।

परीक्षा केंद्रों को किया गया सेनेटराइज

सतना। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए शनिवार को समाजसेवियों द्वारा सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत शासकीय वेंकट उच्चतर माध्यमिक उत्कृष्ट विद्यालय क्रमांक-1 और स्टेशन रोड स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल में परीक्षा केंद्रों को सेनेटराइज किया गया। इस दौरान परीक्षार्थियों को सलाह दी गई कि वे पूर्ण महामारी से निपटने के लिए माक्स का इस्तेमाल अवश्य करें। आपको बता दें कि मौजूदा समय में 12वीं के बचे हुए प्रश्न पत्रों के इम्तिहान चल रहे हैं।

पीईबी के एंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू

कार्यालय संवाददाता, जबलपुर. प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने पीपीटी, पीवी एंड एफटी और डीएएचईटी के एंट्रेंस टेस्ट के ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए कक्षा दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। प्री-पॉलिटेक्निक टेस्ट (पीपीटी) के फॉर्म 25 जून तक जमा किए जाएँगे। एंट्रेंस टेस्ट 25-26 जुलाई को होगा। प्री-वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट (पीवी एंड एफटी) के फॉर्म 23 जून तक जमा किए जाएँगे। ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट 18 व 19 जुलाई को आयोजित किया जाएगा । डिप्लोमा इन एनिमल हसबेंडरी एंट्रेंस टेस्ट (डीएएचईटी) के फॉर्म 23 जून तक जमा होंगे। एंट्रेंस टेस्ट 18 व 19 जुलाई को होगा। प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट (पीएटी) का नोटिफिकेशन भी जल्द ही जारी होगा। इसके फॉर्म 15 से 29 जून तक जमा होंगे। एंट्रेंस टेस्ट 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। पी-4

परीक्षा केंद्र में बिगड़ी छात्रा की तबीयत

सतना। माध्यमिक शिक्षा मंडल की कक्षा 12वीं बोर्ड की परीक्षा दे रही छात्रा तनू त्रिपाठी परीक्षा हॉल में बेहोश हो गई। स्थिति में जब सुधार नहीं हुआ तो उसे बिरसिंहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया गया। बताया गया कि तनू त्रिपाठी निवासी कंदैला का परीक्षा केन्द्र बालक हायर सेकंडरी स्कूल बिरसिंहपुर में था। सुबह 9 बजे परीक्षा प्रारंभ होने के 10 मिनट बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। छात्रा को उल्टी और दस्त होने लगे। केन्द्राध्यक्ष द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में इस आशय की सूचना दी गई। तत्काल परीक्षा हॉल में डॉ. रूपेश सोनी द्वारा छात्रा का इलाज किया गया पर स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो सका,लिहाजा उसे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसिंहपुर में भर्ती कराया गया। बताया गया कि शाम 5 बजे छात्रा के स्वास्थ्य में सुधार होने के बाद उसे डिस्चार्ज किया गया।

एजुकेशन पोर्टल में खामियों से रोष

गांधीग्राम. मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ अध्यापक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष गगन चौबे ने जारी विज्ञप्ति में बताया कि वर्तमान समय में एजुकेशन पोर्टल से कोरी वेतन स्लिप निकल रही है जिस कारण शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है। संघ ने बताया कि वेतन स्लिप की आवश्यकता शिक्षक संवर्ग को अनेक कामों में पड़ती है वहीं कुछ शिक्षकों को स्वयं एवं परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए लोन लेना है या फिर मकान इत्यादि के लिए लोन की आवश्यकता है। ऐसे में एजुकेशन पोर्टल द्वारा निकल रही कोरी पर्चियों से सभी शिक्षक परेशान है। संघ के संजीव शर्मा, बलराम उपाध्याय, विवेक दीक्षित, विनय नामदेव आदि ने आयुक्त से मांग की है कि जल्दी पोर्टल की खामियों को दूर किया जाए।

डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम की परीक्षा अब 17 जुलाई से

भोपाल, (एजेंसी)। राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विवि के अंतर्गत डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम की द्वितीय एवं अंतिम वर्ष के नियमित एवं भूतपूर्व विद्यार्थियों के लिए 22 जून से प्रारंभ होने वाली परीक्षा तिथि को आगे बढ़ाकर 17 जुलाई कर दिया गया है।

डिप्लोमा फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय एवं अंतिम वर्ष के नियमित एवं भूतपूर्व विद्यार्थी 24 जून तक अपनी लॉग इन आईडी. पर जाकर किसी एक शहर का परीक्षा केन्द्र के लिये चयन कर सकते हैं।

राजनीति शास्त्र और वोकेशनल कोर्स की परीक्षा में 136 छात्र अनुपस्थित

12वीं बोर्ड परीक्षा का पाँचवाँ दिन

कार्यालय संवाददाता | जबलपुर

12वीं बोर्ड परीक्षा के पाँचवे दिन शनिवार को राजनीति शास्त्र और वोकेशनल कोर्स के पेपर हुए। दोनों पेपर में 5452 छात्र शामिल हुए जबकि 136 अनुपस्थित रहे। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए परीक्षा केन्द्रों में पूरी सतर्कता बरती जा रही है यही वजह है कि परीक्षा के दौरान अभी तक किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति नहीं बन पाई है। परीक्षा प्रभारी आरके बधान ने बताया कि शनिवार सुबह 9 बजे से राजनीति शास्त्र की परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा में 5227 छात्र शामिल हुए जबकि 115 छात्र अनुपस्थित रहे। वहीं दोपहर 2 बजे से वोकेशनल कोर्स की परीक्षा हुई। जिसमें 225 छात्र शामिल हुए। 21 छात्र परीक्षा से अनुपस्थित रहे। जिले में परीक्षा के दौरान नकल प्रकरण दर्ज नहीं किया गया। सभी छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने और सेनिटाइजर से हाथ साफ करने की हिदायत दी जा रही है। पी-6

बीयू

परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन होगा निरस्त

दूसरे राज्यों में फंसे विद्यार्थी हो रहे परेशान

स्टार समाचार | भोपाल

बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय ने 24 जून से शुरू होने वाली परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाने वाले विद्यार्थियों को आयोजन का विरोधी मानकर इन्हें प्रक्रिया से बाहर करने का फैसला लिया है। कुलपति कार्यालय ने आदेश जारी कर परीक्षाओं का टाइम टेबल सार्वजनिक करते हुए सूचना प्रसारित की है कि परीक्षाओं में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय की ओर से विरोधी मानकर उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाएगा।

दरअसल कुलपति कार्यालय और विद्यार्थी संगठनों के बीच परीक्षाओं के आयोजन को लेकर पिछले कई दिनों से गतिरोध बना हुआ है। प्रबंधन ने से नाराज होकर ऐसा आदेश जारी किया है जिसमें परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय विरोधी करार दे दिया जाएगा।

भोपाल नहीं आ पा रहे

विश्वविद्यालय प्रबंधन और विद्यार्थी संगठनों के बीच चल रही तकरार के बीच दूसरे राज्यों में फंसे ऐसे विद्यार्थी अब परेशान हैं जो कानूनी वजहों से भोपाल आकर परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते। उल्लेखनीय है कि कोरोना संक्रमण के चलते दूसरे राज्यों में फंसे सैकड़ों की संख्या में विद्यार्थी भोपाल नहीं आ पा रहे हैं।

भविष्य दांव पर लगा हुआ

ऐसे मामलों में राजभवन की ओर से यह निर्देश दिए गए थे कि इस प्रकार के विद्यार्थियों की सूची तैयार कर उनकी परीक्षाओं का आयोजन विश्वविद्यालय प्रबंधन अलग से करवाए। कुलपति, प्रबंधन और विद्यार्थी संगठनों के बीच जारी तनातनी के बीच दूसरे राज्यों में फंसे विद्यार्थियों का भविष्य दांव पर लगा हुआ है।

परीक्षाओं का टाइम टेबल नियमों के अनुसार जारी किया गया है। विवि के नियमों के मुताबिक गाइडलाइन तैयार की गई है। अलग से परीक्षाओं के आयोजन को लेकर फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ है।
आरजे राव, कुलपति

वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के कई छात्र ऐसे है जो मध्यप्रदेश के बाहर के जिलों से आते हैं। वे परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाते हैं तो उनके लिए विवि को अलग से परीक्षाओं का आयोजन करवाना चाहिए। परंपरागत मूल्यांकन की जगह वैकल्पिक मूल्यांकन के बारे में भी शासन विचार कर सकता है ,इसके लिए हमने लगातार राज्यपाल, कुलपतियों को भी पत्र लिखा है।
अभिषेक, प्रदेश सहमंत्री
अभाविप परिषद

डीएड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन की तिथि 21 तक

रीवा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा संचालित सत्र 2019-20 की प्रारंभिक शिक्षा में पत्रोपाधि पाठ्यक्रम (डीएड) नियमित प्रथम एवं द्वितीय वर्ष 2020 की परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 21 जून कर दी गई है।

राजनीति विज्ञान की परीक्षा में 268 परीक्षार्थी रहे गैरहाजिर

-निज प्रतिनिधि-

गुना। हायर सेकेंडरी बोर्ड परीक्षा में शनिवार को राजनीति विज्ञान का पेपर आयोजित हुआ। जिसमें 268 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। जबकि इस परीक्षा के लिए कुल 6384 विद्यार्थियों ने फार्म भरा था। शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में हायर सेकेंडरी परीक्षा के तहत सुबह की पाली में राजनीति विज्ञान का पेपर हुआ। जिसमें कुल 6384 विद्यार्थी नामांकित थे लेकिन पेपर देने 6113 ही विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर उपस्थित हुए जबकि 268 अनुपस्थित रहे। वहीं 3 विद्यार्थियों को स्थानांतरित किया गया है। वहीं पूरे पेपर के दौरान कोई भी विद्यार्थी नकल करते हुए नहीं पकड़ा गया।

परीक्षा में उपद्रव करने वालों पर हुई कार्रवाई

जागरण,सीधी। इस समय 12 वीं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। जहां अराजकतत्वों का जमावड़ा लग रहा है। कमर्जी पुलिस ने आज परीक्षा केन्द्र हटवा हायर सेकण्ड्री में परीक्षा के दौरान शांति व्यवस्था भंग करने एवं उपद्रव करने कल्लू सिंह उर्फ सत्यम सिंह पिता राजकुमार सिंह 19 वर्ष निवासी पहाड़ी टिकुरा टोला थाना अमिलिया एवं आकाश सिंह बघेल पिता पंचराज सिंह 20 वर्ष निवासी फरहदा जिला रीवा अपने ननिहाल पहाड़ी टिकुरा टोला थाना अमिलिया आया हुआ था इन दोनो के विरूद्ध कमर्जी पुलिस ने 151 सीआरपीसी के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।

दो पेपरों में 408 विद्यार्थी गैरहाजिर, सोमवार को 4500 देंगे परीक्षा

सागर | माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा शनिवार को आयोजित कक्षा 12वीं की राजनीति शास्त्र तथा व्यावसायिक विषयों की परीक्षा में कुल 408 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। सोमवार को 4500 विद्यार्थी गणित तथा चार व्यावसायिक विषयों की परीक्षा देंगे। इसके लिए जिले में दो पालियों में कुल 109 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. महेंद्र प्रताप तिवारी ने बताया कि शनिवार को सुबह की पाली में राजनीतिशास्त्र विषय में कुल 16032 विद्यार्थियों के लिए 110 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। लेकिन 15701 विद्यार्थी ही परीक्षा देने आए। प्रथम पाली में कुल 331 विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं आए। दूसरी पाली में 7 केन्द्रों पर राजनीति शास्त्र एवं व्यावसायिक विषय में कुल 510 परीक्षार्थियों को परीक्षा में शामिल होना था। लेकिन 433 परीक्षार्थी ही परीक्षा देने आए, 77 परीक्षार्थी गैरहाजिर रहे। सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण रही।

कल गणित और व्यावसायिक विषयों के पेपर

सोमवार को पहली पाली में गणित विषय का पेपर है। 3993 विद्यार्थियों के लिए जिले में 102 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। वहीं दूसरी पाली में हिन्दी शार्टहैंड एवं चार व्यावसायिक विषयों में 507 विद्यार्थी परीक्षा देंगे। इनके लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

कोर्ट के फैसले के बाद शासन को पदोन्नति लाभ देना चाहिए : सपाक्स

सिटी रिपोर्टर | भोपाल

सपाक्स ने कहा है कि अब सरकार को सामान्य, पिछड़ा और अल्पसंख्यक वर्ग के शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ देना चाहिए। तमिलनाडु के राजनीतिक दलों द्वारा लगाई याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आरक्षण 'मौलिक अधिकार' नहीं है। इसके मायने स्पष्ट हैं कि आरक्षण किसी वर्ग विशेष के उत्थान के सकारात्मक कदमों में से एक हो सकता है, लेकिन पहला और एकमात्र कदम नहीं। इस परिप्रेक्ष्य में मप्र उच्च न्यायालय के पदोन्नति में आरक्षण को लेकर दिए गए निर्णय का संज्ञान लेना सामयिक है।

सपाक्स के अनुसार न्यायालय ने 30 अप्रैल 2016 के निर्णय में मप्र पदोन्नति नियम 2002 खारिज कर दिए थे, क्योंकि इन नियमों को असंवैधानिक पाया था, लेकिन तत्कालीन सरकार, जिससे अपेक्षा थी कि कानून का सम्मान करते हुए निर्णय लागू करेगी, दबाव और राजनीतिक लाभ के लिए सर्वोच्च न्यायालय चली गई। विगत 4 वर्षों से सरकार की यह अपील लंबित है, लेकिन सरकार ने कभी इसके निपटारे की पहल नहीं की, जबकि हजारों कर्मचारी इस अवधि में पदोन्नति के वाजिब अधिकार से वंचित कर दिए गए और उन्हें सरकार ने उन वरिष्ठ पदों पर बैठाए रखा, जो वास्तव में हकदार नहीं थे। यह स्थिति आज तक विद्यमान है। प्रश्न यह है कि क्या खुद सरकार संविधान का पालन करना नहीं चाहती? इसका उत्तर सपाक्स संस्था दोनों प्रमुख दलों से जानना चाहती है।

राजनीति शास्त्र के प्रश्न पत्र में पानबिहार के केंद्र पर बना नकल प्रकरण

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

12वीं की स्थगित प्रश्न पत्रों की परीक्षा अब कोरोना संक्रमण के बीच चल रही है। शनिवार को राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा में शासकीय उमावि पानबिहार के परीक्षा केंद्र पर एक छात्र प्रश्न पत्र के भीतर नकल पर्चियां रखकर नकल करते हुए रंगेहाथों पकड़ाया। नकल पर्चियां व कॉपी लेकर उसका प्रकरण बनाया गया। स्थगित परीक्षाओं के बीच जिले में नकल का यह पहला मामला है। इसके अलावा संत मीरा कन्या उमावि में एक विद्यार्थी में कोरोना के लक्षण होने के कारण उसे आइसोलेशन कक्ष में बैठाकर परीक्षा दिलवाई गई। राजनीति शास्त्र विषय में जिले में 6671 विद्यार्थियों में से 6223 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। 448 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे।

परीक्षा और रिजल्ट की तरह री-टोटलिंग भी लेट

ग्वालियर|कोरोना संक्रमण के चलते एमपी बोर्ड की परीक्षा, रिजल्ट और री-टोटलिंग की प्रक्रिया अस्त-व्यस्त हो गई है। अभी तक सिर्फ कक्षा 9वीं व 11वीं कक्षा का रिजल्ट ही घोषित हुआ है। कक्षा 10वीं के छात्रों का रिजल्ट भी जल्द घोषित होने को है जबकि कक्षा 12वीं के छात्रों की परीक्षाएं 16 जून तक चलेंगी। सभी परीक्षाओं का रिजल्ट आने के बाद एक महीने का समय री-टोटलिंग के लिए रहेगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी होगी। सूत्रों के मुताबिक इस साल री-टोटलिंग का काम विलंब से हो रहा है।

130 छात्रों ने नहीं दी राजनीति शास्त्र की परीक्षा

जिले के 98 केंद्रों में हुआ बोर्ड परीक्षा का आयोजन

जागरण, रीवा। माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा शनिवार को पहली पाली में 12वीं के राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा कराई। जबकि दूसरी पाली में शरीर रचना क्रिया-विज्ञान व स्वास्थ्य व्यावसायिक द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा हुई। इस परीक्षा में 6 हजार 26 नियमित छात्र उपस्थित रहे, जबकि 130 छात्रों की अनुपस्थिति दर्ज की गई। परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्रों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई गई। गौरतलब है कि मार्च माह में 12वीं की उक्त परीक्षा कोरोना महामारी से बचाव के लिए स्थगित कर दी गई थी। अब लॉकडाउन खुलने पर फिर से 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं संचालित हैं।

शनिवार को परीक्षा के पांचवें दिन सभी 98 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन हुआ। बताया गया कि गुरूवार को राजनीति शास्त्र विषय की परीक्षा 906 स्वाध्यायी को देना था, जिसमें से 774 हाजिर व 132 स्वाध्यायी छात्र गैर हाजिर रहे। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह का नकल प्रकरण नहीं बना। परीक्षा का निरीक्षण के लिए जिला स्तर पर गठित तीन पैनल कई स्कूलों तक पहुंचे। इसमें पहले पैनल ने शासकीय विद्यालय बालक हनुमना, कन्या विद्यालय हनुमना व शासकीय विद्यालय खटखरी का निरीक्षण किया। दूसरे पैनल ने शासकीय विद्यालय बालक गंगेव, शासकीय हाईस्कूल कन्या गंगेव, आदर्श नर्मदा विद्यालय तथा मॉडल स्कूल गंगेव का भ्रमण किया। तीसरे दल ने शासकीय विद्यालय लक्ष्मणपुर, शासकीय विद्यालय क्रमांक 2 एवं बीएनपी स्कूल का जायजा लिया। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को कक्षा में प्रवेश के पहले जांच से गुजरना पड़ा। छात्रों की जांच के लिए कर्मचारियों को तैनात किया गया था। छात्रों को सेनेटाइज करने के साथ ही थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। कक्ष में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया गया। एक बेंच पर सिर्फ एक छात्र को ही बैठाया गया।

पेपर बिगड़ा तो 12वीं के छात्र ने फांसी लगाई, मौत

भास्कर संवाददाता | उज्जैन

ढांचा भवन निवासी राहुल राव मराठा (18) ने फांसी लगाकर जान दे दी। वह 12वीं का छात्र था और 9 जून को केमेस्ट्री का पेपर बिगड़ गया था, इसी को लेकर वह दुखी था।

चिमनगंज थाने के प्रधान आरक्षक गौरीशंकर ने बताया राहुल के परिजनों के बयान नहीं हुए हैं, उन्होंने फिलहाल बात करने से इनकार कर दिया। सिर्फ यहीं कहा कि बेटे का पेपर बिगड़ने की वजह से ही वह दुखी था और संभवतः इसी कारण उसने आत्महत्या कर ली। परिवार में माता-पिता के अलावा एक छोटा भाई है। पिता लक्ष्मण राव ऑटो चालक है। वह घर पर नहीं थे। उनकी पत्नी भी छोटे बेटे को डॉक्टर को दिखाने लेकर गई थी जो वापस लौटी तो बेटे को फंदे पर लटका देख पुलिस को सूचना दी।

दीवार गिराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट : वृंदावनपुरा कॉलोनी में घर की दीवार गिराने को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। जीवाजीगंज पुलिस भी मौके पर पहुंची। धर्मेंद्र माली की रिपोर्ट पर छोटू, व धर्मेंद्र देवीसिंह व सीताराम की रिपोर्ट पर धर्मेंद्र व रमेशचंद्र पर केस दर्ज किया है।

मप्र में स्कूल खोले जाने का फैसला16 के बाद

भास्कर न्यूज भोपाल।

मध्यप्रदेश में स्कूल खोले जाने का फैसला 16 जून के बाद लिया जाएगा। इस बारे में संकेत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शनिवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में दिए हैं। सीएम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के महिला स्व-सहायता समूहों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में महिला स्व-सहायता समूहों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार द्वारा उन्हें विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के लिए आगामी समय में 1433 करोड़ रूपए के कार्य दिलाए जाएंगे। स्व-सहायता समूहों की महिलाएं अपने गांव और क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय वस्तुओं का निर्माण करें। उन्हें बाजार उपलब्ध कराने में भी सरकार उनकी मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में महिला स्वसहायता समूहों से अपने क्षेत्र और गांव को जगरूक बनाने का आह्वान किया। सीएम ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत का विद्यार्थियों के लिए ड्रेस बनाए जाने का कार्य दिए जाने की बात कही।

स्कूल शिक्षा विभाग ने उम्मीदवारों से मांग ली संबंधित विषय में डिग्री

1500 अध्यापकों का संविलियन अधर में नए कैडर के साथ 10 हजार का नुकसान

मेरा हक

भोपाल/इंदौर • डीबी स्टार

सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग ने शिक्षाकर्मियों को रखा है। शासन ने नौकरी देते वक्त इस बात की पड़ताल नहीं की कि उन्होंने किस विषय में ग्रेजुएशन किया है। सिर्फ डिग्री के आधार पर उन्हें नियुक्ति दे दी गई। जब बात उन्हें नया कैडर देने की आई तो नियम खंगाले जा रहे हैं। बताया जाता है कि संबंधित विषय में डिग्री न होने पर शिक्षाकर्मियों के माध्यमिक शिक्षक के पद पर संविलियन का मामला खटाई में पड़ गया है। इसके परिणाम स्वरूप प्रदेश भर के लगभग 1500 अध्यापकों का संविलियन नहीं हो पा रहा है। इसके चलते उन्हें बढ़ा हुआ वेतन और अन्य भत्तों का लाभ भी नहीं मिल रहा है।

संविलयन नहीं हुआ तो प्रमोशन भी नहीं

शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षकों को सातवां वेतनमान दिया है। उनका मौजूदा वेतन 9300-34800-3600 रुपए प्रतिमाह है। बगैर संविलियन वाले शिक्षक 9300-34800-3200 का वेतन है। इस तरह हर माह उन्हें लगभग दस हजार रुपए का नुकसान हो रहा है। उन्हें माध्यमिक शिक्षकों की तरह अन्य सुविधाएं भी नहीं मिल रही। इसमें सिटी कन्वेंस अलाउंस, एचआरए, ग्रेज्युटी अनुकंपा नियुक्ति और ग्रुप इंश्योरेंस शामिल हैं। नए कैडर में नहीं आने से वे माध्यमिक शिक्षकों की वरीयता सूची से भी बाहर हैं। साथ ही वे पदोन्नति के लाभ से भी वंचित रह जाएंगे।

02 लाख 80 हजार अध्यापक प्रदेश में

15 सौ शिक्षकों का संविलियन बाकी

1 कीर्ति गीते की नियुक्ति जिला पंचायत, धार ने 1998 में वर्ग-2 में की थी। वे इंदौर के एक मिडिल स्कूल में पदस्थ हैं और होम साइंस में स्नातक हैं। उन्होंने सामाजिक विज्ञान में एमए किया है, लेकिन विभाग उनसे सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन की डिग्री मांग रहा है।

2 सीमा अलावा की नियुक्ति जिला पंचायत, मंदसौर ने वर्ग-2 में विज्ञान विषय में 2001 में की थी। वे शासकीय माध्यमिक विद्यालय, कांकरिया (मानपुर) में पदस्थ हैं और होम साइंस में स्नातक हैं। विज्ञान विषय की डिग्री न होने से वे माध्यमिक शिक्षक नहीं बन पा रही हैं।

3 सरिता मिश्रा की नियुक्ति सांवेर जनपद पंचायत ने वर्ग-2 में विज्ञान विषय में की थी। उनके पास भी स्नातक होम साइंस की डिग्री है। विभाग ने उनका माध्यमिक शिक्षक के पद पर संविलियन रोक रखा है। उनसे संबंधित विषय की डिग्री मांग रहे हैं।

जो विषय पढ़ा रहे हैं उसमें मांग रहे डिग्री

अध्यापक से माध्यमिक शिक्षक बनाने के लिए संविदा शाला शिक्षक नियम की अधिसूचना 2005 और 2011 को आधार मान रहे हैं। इसके तहत वर्ग-2 अध्यापक को संबंधित विषय में स्नातक होना जरूरी है। इस कारण वे अध्यापक माध्यमिक शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं, जिनके पास नियुक्ति आदेश में दर्ज विषय की डिग्री नहीं है। इसमें सबसे अधिक संख्या उन शिक्षकों की है, जिन्होंने होम साइंस, फिजिकल एजुकेशन और कम्प्यूटर विषय से स्नातक किया है।

ऐसे समझें अध्यापक संवर्ग के संविलियन का मामला

शिक्षा विभाग ने 18 जुलाई, 2018 को अधिसूचना जारी की थी। इसके तहत मप्र स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षणिक संवर्ग) नाम से नया कैडर बनाया है। इसमें अध्यापक संवर्ग का संविलियन किया गया है। सहायक अध्यापक को प्राथमिक शिक्षक, अध्यापक को माध्यमिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापक को उच्च माध्यमिक शिक्षक माना गया है। अध्यापक संवर्ग के शिक्षक पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के कर्मचारी थे। उनकी नियुक्तियां, जनपद और जिला पंचायत स्तर पर शिक्षाकर्मी के रूप में 1998 में हुई थी। 2007 में पंचायत विभाग ने उन्हें शिक्षाकर्मी से अध्यापक बना दिया। इसी कैडर के कई अध्यापक (वर्ग-2) अब माध्यमिक शिक्षक नहीं बन पा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है विभाग इसके लिए नियम का हवाला दे रहा है।

अध्यापकों की समस्या का समाधान किया जाएगा

अध्यापकों के साथ विषयों को लेकर विसंगति का मामला अफसरों से पता कराती हूं। यदि हमारे यहां इस संबंध में कोई फाइल पेंडिंग है तो उसका समाधान करेंगे। बेहतर होगा कि आप किसी भी एक शिक्षक का रिकॉर्ड भिजवा दीजिए। यदि मामले में कोई पॉलिसी डिसीजन लेना है तो वह भी लेंगे। अध्यापकों की समस्या का निराकरण जल्द ही किया जाएगा।

जयश्री कियावत, आयुक्त, लोक शिक्षण

शिक्षक भर्ती : 16 से 30 जून तक अपलोड करना होंगे दस्तावेज

भोपाल/इंदौर • डीबी स्टार

उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती के लिए आदिम जाति कल्याण विभाग ने सफल उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उसमें फर्स्ट राउंड की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और वेटिंग लिस्ट शामिल है। यह लिस्ट 2220 पदों के लिए जारी की गई। विभाग ने वेटिंग लिस्ट में भी इतने ही उम्मीदवारों को शामिल किया है। अब उम्मीदवार पोर्टल https://trc.mponline.gov.in पर 16 से 30 जून तक दस्तावेज ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। साथ ही स्कूलों के विकल्प का चयन करना होगा। सत्यापन की प्रक्रिया 8 से

20 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद अंतिम चयन सूची जारी की जाएगी। स्कूल शिक्षा विभाग 15 हजार पदों की भर्ती के लिए एक ही राउंड में एक साथ भर्ती कर रहा है। आदिम जाति कल्याण विभाग 5740 पदों पर भर्ती करेगा।

सामान्य प्रशासन विभाग ने 2016 में दिया था आदेश, नियमों में उलझे हैं आदिम जाति कल्याण विभाग के अफसर

236 दैनिक वेतनभोगियों को चार साल बाद भी न पद और न वेतनमान, हर माह पांच हजार रु. का नुकसान

मेरा पैसा

इंदौर • डीबी स्टार

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के चार साल बाद भी आदिम जाति कल्याण विभाग इंदौर में चतुर्थ श्रेणी के 236 दैनिक वेतनभोगियों को स्थायीकर्मी का पद और विनियमित वेतनमान नहीं मिला है। विभाग के अफसर अब तक नियमों में ही उलझे हैं और कर्मचारियों को हर माह औसतन पांच हजार का नुकसान हो रहा है। इसके विपरीत सागर और छतरपुर में कर्मचारियों को वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है।

2016 तक के सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं पात्र

सामान्य प्रशासन विभाग के 7 अक्टूबर 2016 के आदेश में कहा गया है कि वह सभी दैनिक वेतनभोगी जो 16 मई 2007 और 1 सितंबर 2016 को कार्यरत थे, उन्हें स्थायीकर्मी का पद दिया जाए। 16 मई 2007 के बाद शासन की अनुमति से सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त हुए दैनिक वेतनभोगी भी पात्र होंगे, लेकिन इंदौर में 2007 से पहले या उसके बाद के किसी भी दैनिक वेतनभोगी को इसका लाभ नहीं मिला है।

शिकायत ने उलझाया मामला, अफसर नहीं ले सके फैसला

इंदौर में विभाग की सहायक आयुक्त मोहिनी श्रीवास्तव ने वर्ष 2017 में 236 कर्मचारियों को विनियमित करने का आदेश निकाला था। इसमें 2007 से पहले और उसके बाद के सभी कर्मचारी शामिल थे। कर्मचारियों के मुताबिक कुछ जिलों में 2007 तक के कर्मचारियों को ही स्थायी कर्मी का पद दिया गया है, इसलिए वहां के कर्मचारियों ने इंदौर की तरह 2016 तक के कर्मचारियों को भी विनियमित करने की मांग की। शिकायत हुई तो मामला शासन तक पहुंचा। जांच बैठी। रिपोर्ट भोपाल भी पहुंची, लेकिन फैसला नहीं हुआ। अफसर नियमों में ही उलझे रहे। नतीजतन, कोई भी स्थायी नहीं हो सका।

आदेश के बावजूद फायदा नहीं

कुछ समय पहले सहायक आयुक्त मोहिनी श्रीवास्तव ने 2007 से पहले के 51 दैनिक वेतनभोगियों को विनियमित करने का नया आदेश निकाला है। उनका कहना है कि छह महीने से विभाग से अलॉटमेंट मांग रही हैं, लेकिन राशि नहीं मिली है, इसलिए वेतनमान नहीं दिया जा रहा है।

बढ़ा वेतन मिलता उससे पहले मौत

जानकीबाई ठाकुर जिला उत्कृष्ट बालक छात्रावास, संयोगितागंज में कुक थीं। दिसंबर में रिटायरमेंट था, लेकिन 10 जून 2020 को निधन हो गया। उन्हें 7950 रुपए मिलते थे। इसमें से दस फीसदी राशि नेशनल पेंशन स्कीम (एनपीएस) की कट रही थी। वेतनमान मिलता तो महंगाई भत्ता और डीए मिलाकर उनका वेतन 14 हजार 833 रुपए होता। दस फीसदी कटौती के बाद 13 हजार 349 रुपए उनके हाथ में आते। यानी वह 6 हजार 194 रुपए का नुकसान उठाकर नौकरी करती रहीं।

हर माह सात हजार रु. का नुकसान

प्रेमलता यादव नवीन प्री मैट्रिक अजा बालक छात्रावास, संगमनगर में कार्यरत हैं। उन्हें 7950 रुपए मिलते हैं। दस फीसदी एनपीएस के कट रहे हैं। विनियमित वेतनमान में यह राशि 15 हजार 849 रुपए बनती। दस फीसदी एनपीएस कटौती के बाद उन्हें 14265 रुपए मिलते। यानी उन्हें हर महीने 7 हजार का नुकसान हो रहा है।

अफसरों की लापरवाही है इसमें

गौरव यादव, धन्नालाल चौहान, जितेंद्र मालवीय व अन्य कर्मचारियों ने बताया सामान्य प्रशासन विभाग ने हमें स्थायीकर्मी का पद देने के साथ विनियमित करने के आदेश दिए हैं। अधिकारी 2007 और 2016 में उलझे हैं। इससे हमें हर महीने 5 हजार का नुकसान हो रहा है। अफसरों की लापरवाही से हमें हक नहीं मिल रहा है।

सीधी बात

मोहिनी श्रीवास्तव
सहायक आयुक्त

सरकार से मांगी है अनुमति

• दैनिक वेतनभोगियों को विनियमित वेतनमान क्यों नहीं मिल रहा है?

- शासन ने कहा था कि 2007 से पहले के श्रमिकों को स्थायीकर्मी बनाया जाए, पर तब श्रमिकों की दस साल की सेवा पूरी नहीं हुई थी। इसलिए नहीं कर पाए।

• नियम तो 2016 तक के कर्मचारियों को भी स्थायी करने का है। फिर ऐसा क्यों?

- हमने शासन से अनुमति मांगी थी। कहा गया कि जिला स्तर पर निर्णय लें। हमने सभी स्थायी कर्मी का पद दे दिया तो आपत्ति आ गई।

• 2007 के बाद के दैनिक वेतनभोगियों को लेकर क्या मनाही हो गई है?

विभाग ने निरस्ती के बारे में नहीं लिखा है। ।

• 2007 से पहले वालों को भी बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिल रहा है। ऐसा क्यों?

हमने अलॉटमेंट मांगा है। बजट आने पर वेतनमान देंगे।

आदेश है तो उनका पालन कराएंगे

दैनिक वेतनभोगियों को वेतनमान नहीं देने का मामला दिखवाएंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के ऐसे आदेश हैं तो उसका पालन कराया जाएगा।

बी. चंद्रशेखर आयुक्त, आदिम जाति कल्याण

तीन एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन जारी

पीपीटी के फॉर्म 25 जून तक ऑनलाइन जमा होंगे

इंदौर/भोपाल • **डीबी स्टार**

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड (पीईबी) ने तीन एंट्रेंस एग्जाम कराने के लिए नोटिफिक्केशन जारी कर दिए हैं। इनके ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। पीईबी ने पीपीटी, डीएएचईटी और पीवी एंड एफटी की रूल बुक जारी की हैं। इन एंट्रेंस टेस्ट में शामिल होने के लिए कक्षा दसवीं और बारहवीं के रिजल्ट के इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रिजल्ट के बिना भी स्टूडेंट्स फार्म जमा कर सकते हैं। एंट्रेंस एग्जाम को लेकर पीईबी के पोर्टल www.peb.mp.gov.in से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कब-कौन सा टेस्ट

- ***प्री-पॉलिटेक्निक टेस्ट*** *(पीपीटी) के फॉर्म 25 जून तक जमा होंगे। टेस्ट 25-26 जुलाई को होगा।*

- ***प्री-वेटरनरी एंड फिशरी टेस्ट*** *(पीवी एंड एफटी)-2020 में फॉर्म 23 जून तक जमा होंगे। ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट 18 व 19 जुलाई को होगा।*

- ***डिप्लोमा इन एनिमल हसबेंडरी एंट्रेंस टेस्ट*** *(डीएएचईटी)-2020 के फॉर्म 23 जून तक जमा होंगे। एंट्रेंस टेस्ट 18 व 19 जुलाई को होगा।*

- ***प्री-एग्रीकल्चर टेस्ट*** *(पीएटी) का नोटिफिक्केशन भी जल्द ही जारी होगा। इसके फॉर्म 15 से 29 जून तक जमा होंगे। टेस्ट 8 अगस्त को आयोजित किया जाएगा।*